















Relevant Provisions in the New Criminal Laws

A child may be referred to a CWC for rehabilitation and social integration in cases where he/she is an orphan, abandoned, lost, voluntarily given away by the parents, or the offspring of mentally retarded parents, or an unwanted child of victim of sexual assault or is affected due to offences against him/her under the following Sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) –

- Sections 63 and 64 Regarding rape and its punishment.
- Section 65 Regarding punishment for rape in cases wherein the age of the girl is less than sixteen years or the girl is under twelve years of age.
- Section 68 Regarding sexual intercourse by a person in authority.
- Section 70 Regarding gang-rape.
- Section 72 Regarding disclosure of identity of victim of certain offences (rape, gang-rape, sexual intercourse) which restricts the printing or publishing the name or any matter which may make known the identity of any person.







नए आपराधिक कानूनों में प्रासंगिक प्रावधान

किसी बच्चे को ऐसे मामलों में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए बाल कल्याण सिमित में भेजा जा सकता है जब वह अनाथ है, परित्यक्त है, खोया हुआ है, माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिया गया है, या मानसिक रूप से विकलांग माता-पिता की संतान, या यौन उत्पीड़न के शिकार का अवांछित बच्चा है या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की निम्नलिखित धाराओं के तहत उसके खिलाफ हुए अपराध से वह प्रभावित है –

- धारा ६३ और ६४ बलात्कार और उसकी सजा के संबंध में।
- धारा 65 उन मामलों में बलात्कार के लिए सजा के संबंध में जिनमें महिला की उम्र सोलह वर्ष से कम है या महिला की उम्र बारह वर्ष से कम है।
- धारा ६८ प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
- धारा 70 सामृहिक बलात्कार के संबंध में।
- धारा 72 कुछ अपराधों (बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन संबंध) की पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के संबंध में है जो नाम या किसी ऐसे मामले को छापने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है।







- Section 73 Regarding printing or publishing any matter relating to court proceedings on rape, gang-rape and sexual intercourse without permission.
- Section 93 to 99 Regarding offences against child.
- Sections 137 to 146 Regarding kidnapping, abduction, slavery and forced labour.

Further, those who are in conflict with the law are put in observation homes for further rehabilitation.







- धारा 73 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और यौन संबंध पर अदालती कार्यवाही से संबंधित
 किसी भी मामले को बिना अनुमित के छापने या प्रकाशित करने के संबंध में।
- धारा ९३ से ९९ बालकों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में।
- धारा १३७ से १४६ व्यपहरण, अपहरण, गुलामी और जबरन श्रम के संबंध में। इसके अलावा, वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें आगे के पुनर्वास के लिए अवलोकन गृहों में रखा जाता है।

